लॉन्ग टर्म सिंचाई फंड - भारतीय सिंचाई के लिए दीर्घकालिक लाभ

सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की आरंभिक कोष के साथ नाबार्ड में लंबी अवधि के सिंचाई कोष (एलटीआईएफ़) की स्थापना जो धन के अभाव में अधूरा सड़ रहे थे - 2016-17 के केंद्रीय बजट में एक पथ सिंचाई के क्षेत्र में घोषणा तोड़ने बनाया बहुत सालौ के लिए। इस घोषणा के साथ, पूरा व्यावसायिकता और गति नाबार्ड रुपये मंजूर प्रदर्शित के अनुसार। 21488 64 परियोजनाओं के लिए केंद्रीय शेयर के प्रति ऋण के रूप में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) को करोड़। इस के खिलाफ, रुपये के संवितरण की। 1500 करोड़ भी नई दिल्ली में 21 एनडब्ल्यूडीए करने के लिए बनाया अक्टूबर 2016 और अधिक पढ़ें। Rs.10,853 के बाद में, नाबार्ड की मंजूरी दी है ऋण राशि गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों करोड़ रुपये। करोड़ 2981 रुपए की ऋण सहायता भी आंध्र प्रदेश में ऐतिहासिक पोलावरम परियोजना के लिए एनडब्ल्यूडीए करने के लिए केन्द्रीय सहायता की दिशा में मंजूर की गई है। इस के साथ, नाबार्ड द्वारा संचयी प्रतिबंधों रुपये पर पहुंच गया है। एलटीआईएफ़ के तहत 35,322 करोड़ रुपये रहा। संचयी नाबार्ड द्वारा वितरित राशि रुपये 5671 करोड़ तक पहुँच गया है।

एलटीआईएफ़ के तहत कुल प्रतिबंधों अब तक के साथ, संचयी क्षेत्र इन परियोजनाओं के तहत सिंचाई किए जाने के लिए एक प्रभावशाली 46.48 लाख हेक्टेयर हो तक पहुंच जाएगा।